THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir, The Minister of Trade and Industry, South Africa during his recent visit to India had a meeting with the Minister of State for Commerce, wherein various bilateral matters were discussed.

(c) No protocol/MOU on mining of manganese, gold, iron-ore, chrome and liquification of gas etc. has been signed between India and South Africa. No negotiations are in progress in this regard.

Child Labour in Karnataka

2060. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what is the total number of child labour estimated in Karnataka as on date;

(b) which are the industries where the child labour are working in Karnataka; and

(c) what are the steps taken to abolish child labour in Karnataka and whether the State-level child labour advising committee is functioning in Karnataka, if so, who are its members?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Border Area Development Programme in West Bengal

2061. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what amount of money has been spent, district-wise, under Border Area Development Programme in West Bengal during 1993-94 and 1994-95; and

(b) what schemes have been implemented so far for the socio economic upliftment of the people of Border Areas of the State under the BADP?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA): (a) and (b) Schemes under Border Area Development Programme (BADP) are operated in blocks in West Bengal lying on Bangladesh border. Funds under BADP are released to the State Government and a Committee at the State level decides on sectoral and spatial allocations. Schemes such as construction of flood relief shelters; construction of community centres; development of schools and libraries; creation of non-conventional energy sources; construction of market complexes; development of play-grounds; sinking of tubewells for potable water; sinking of tubewells for irrigation purpose; development of infrastructural facilities in the health institutions; repair–renovation of local roads; improvement of training facilities for blind boys and development of infrastructural facilities in juvenile home etc. have been implemented under BADP in West Bengal in 1993-94 and 1994-95. District-wise allocations during 1993-94 and 1994-95 are annexed.

Statement

District-wise allocation of Funds under BADP in West Bengal for the years 1993-94 and 1994-95

District	Amount (Rs. in lakh)
South 24-Parganas	639.150
North 24-Parganas	355.210
Nadia	300.006

District	Amount (Rs. in lakh)
Murshidabad	694.630
Malda	427.305
Dakshin Dinajpur	728.790
Uttar Dinajpur	495.060
Cooch Behar	563.946
Jalpaiguri	237.760
Darjeeling	108.360

ताप बिजली घरों को कोयले की कम आपूर्ति

2062. **श्री सोमपाल:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयले के कम उत्पादन और इसकी ढुलाई की समस्याओं के कारण देश के विभिन्न ताप बिजली घरों में उपलब्ध कोयले के भण्डार केवल कुछ ही दिनों के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इन बिजली घरों में कोयले के भण्डारों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) देश में अप्रैल-नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि० (को०इं० लि०) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० (सि०को०कं०लि०) से विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को वास्तविक रूप में किए गए कोयले के प्रेषण 115.88 मिलियन टन (अनंतिम) रहा, जबकि इस अवधि के लिए लक्ष्य 116.52 मिलियन टन रखा गया था। इस संबंध में लक्ष्य की प्राप्ति 99.45% रही और विद्युत गृहों के पास कोयले का कम स्टाक होने के कारणों में, निम्नलिखित कारण शामिल हैं:—

(1) कोयले का मात्रा की तुलना में अधिक उपभोग, जोकि कोयला कंपनियों द्वारा इन विद्युत गृहों को आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(2) विद्युत गृहों के स्थलों पर कोयले के उतराई संबंधी अवरोध।

(3) विद्युत गृहों द्वारा कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि की अदायगी न किए जाने के कारण कोयले की आपूर्ति प्रतिबंधित की जा रही है।

(4) रेलवे का संचलन संबंधी अवरोध; और

(5) सिं० को०कं०लि० में छुटपुट हड़ताल होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो रही है और देश के पूर्वी भागों में कुछ खानों का जलमग्न होना है।

(ख) देश में 65 विद्युत गृहों के पास कोयले का कुल स्टाक, जिस पर कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है, यह 12-12-1995 की स्थिति के अनुसार 2.947 मिलियन टन था।

कोयला कंपनियां, कोयले के उत्पादन को अधिकतम किए जाने के प्रयास कर रही हैं और ये इसकी सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति करती हैं, जिसमें विद्युत गृह भी शामिल है, जोकि योजना आयोग के साथ किए गए परामर्श के अनुसार वार्षिक योजना को दिए गए अंतिम रूप के अनुसार की जाती है। विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है और इस मामले में एक अंतर-मंत्रालयीय समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। इस बारे में जहां कहीं भी अपेक्षित होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। किन्तु, कोयले का स्वतंत्र रूप में आयात किया जा सकता है और विद्युत गृह सहमति हुए स्तर से ऊपर की मांग में हुई किसी तरह की वृद्धि को पूरा किए जाने हेतु आयातों के माध्यम से अपनी आपूर्ति की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। विद्युत का उत्पादन किए जाने का भी विकल्प अब उपलब्ध है।

Proposal for creation of separate departments of consumer affairs

2063. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have asked the State Governments to create a